

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEASI TIMES हिन्दी

सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स



CEASI TIMES



दुग्ध, खाद्य सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए असम कैबिनेट ने लिए अहम फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें मंजूर की हैं। इस बैठक की सबसे बड़ी घोषणा रानी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म मैनेजमेंट परिसर में AMUL द्वारा अत्याधुनिक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति है।

कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 20 बीघा जमीन लीज पर दी है। यह प्लांट रोजाना 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगा। इसकी लागत ₹75 करोड़ से ₹150 करोड़ के बीच होगी और इससे लगभग 20,000 डेयरी किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण आय और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। यह कदम एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में AMUL के साथ हुए समझौते के तहत उठाया गया है।

कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मंजूरी दी, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। इसके साथ ही ICT प्रशिक्षकों के कल्याण के लिए वित्तीय लाभों की घोषणा की गई। इसके अलावा IIPA के तहत प्रमुख निजी निवेश को भी मंजूरी दी गई, जिससे 1,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आंध्र प्रदेश का लक्ष्य - स्मार्ट और टिकाऊ पशुपालन का वैश्विक केंद्र बनना

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को स्मार्ट और टिकाऊ पशुपालन का वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा जताई है। विजयवाड़ा में आयोजित पशुपालन सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत देसी नस्लों को बढ़ावा देने, अधोसंरचना के आधुनिकीकरण और डेयरी किसानों को तकनीक आधारित प्रशिक्षण देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 11% से अधिक योगदान पशुधन क्षेत्र से आया है।



उन्होंने यह भी दोहराया कि आंध्र प्रदेश को तकनीक आधारित ग्रामीण विकास का मॉडल बनाकर "स्वर्ण आंध्र प्रदेश" 2047 के लक्ष्य में बड़ा योगदान दिया जाएगा।

नायडू ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कई मामलों में अग्रणी है—अंडा उत्पादन में पहला, मांस में पांचवां और दूध उत्पादन में सातवां स्थान। उन्होंने नवाचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कृषि व पशुपालन में टिकाऊ विकास और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक को अपनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने 'गाय आधार' योजना की 96% सफलता दर की जानकारी दी, जिससे पशुओं की पहचान और प्रबंधन आसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि अब एआई तकनीक की मदद से पक्षियों की आवाजों से भी पशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है।

CEASI TIMES

त्रिपुरा को पशुपालन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र का पूरा सहयोग

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने त्रिपुरा को दूध और मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। पश्चिम त्रिपुरा के बामुटिया में एक आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन पर बोलते हुए, उन्होंने बताया कि भारत में दूध उत्पादन में सालाना 6% की वृद्धि हो रही है, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 2% है। उन्होंने त्रिपुरा में पशुपालन और मत्स्य पालन की मजबूत संभावनाओं को भी रेखांकित किया।



त्रिपुरा लंबे समय से खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास कर रहा है और 2002-03 से लक्ष्य तय कर चुका है। हालांकि, पहले के प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं ला सके। कई योजनाओं के बावजूद, राज्य अब भी मांस, दूध और अंडों के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है। मंत्री के इस आश्वासन के साथ अब त्रिपुरा के पास दुग्ध और मत्स्य क्षेत्र में सुधार कर सतत विकास और ग्रामीण समृद्धि प्राप्त करने का एक नया अवसर है।

नया संयंत्र प्रतिदिन 40,000 लीटर दूध की प्रोसेसिंग कर सकता है, जिसमें 10,000 लीटर दही और छाछ के लिए है। मंत्री ने त्रिपुरा से वाराणसी मॉडल अपनाने और खुर और मुंह रोग पर नियंत्रण करने का आह्वान किया ताकि राज्य डेयरी निर्यात में आगे बढ़ सके।



पशुपालन विभाग ने मिलावट, नस्ल सुधार और डेयरी नवाचार में NDRI से सहयोग मांगा

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) की सचिव अल्का उपाध्याय, आयुक्त डॉ. अभिजीत मित्रा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करनाल स्थित ICAR-NDRI संस्थान का दौरा किया। टीम ने वहां वैज्ञानिकों से बातचीत की और डेयरी क्षेत्र में NDRI के लंबे समय से दिए योगदान की सराहना की। उपाध्याय ने मिलावट पहचान किट, गर्भावस्था परीक्षण उपकरण और किसानों को केंद्र में रखकर जानकारी पहुंचाने की गतिविधियों में सहयोग की इच्छा जताई।

उन्होंने असम की लखिमी गाय की नस्ल के विकास पर भी जोर दिया, जो जलवायु के अनुकूल मानी जाती है। साथ ही उन्होंने रोग रोकथाम, आनुवंशिक सुधार और डेयरी क्षेत्र के विकास में मिलकर काम करने की आवश्यकता बताई। डॉ. मित्रा ने पशु और मानव स्वास्थ्य के एकीकृत दृष्टिकोण तथा पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति DAHD की प्रतिबद्धता दोहराई।

NDRI के निदेशक डॉ. धीरे सिंह ने संस्थान की 102 वर्षों की विरासत साझा की, जिसमें 144 तकनीकों का विकास, 71 का व्यावसायीकरण और 56 पेटेंट शामिल हैं। दौरे का समापन डॉ. आशीष कुमार सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने DAHD के साथ आगे भी सहयोग जारी रखने की आशा व्यक्त की।

CEASI TIMES



35% सब्सिडी के साथ यूपी में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में अहम बदलावों को मंजूरी दी है। इसके तहत डेयरी यूनिट्स की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए सब्सिडी को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, जो अधिकतम ₹5 करोड़ तक होगी। यह कदम निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अब यह नई सब्सिडी राज्य की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 के अनुरूप है। इसके तहत डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण पर 35% या ₹2.5 करोड़ तक की सहायता मिलेगी। मशीनरी और उपकरण खरीदने पर ₹1 करोड़ तक की मदद दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को उनकी अपनी कमाई (जैसे मछली पालन) के पांच गुना तक की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और ग्राम शासन को मजबूत करना है।

शिवराज सिंह चौहान ने नागालैंड में पशु चिकित्सक कॉलेज का उद्घाटन किया और ₹338.83 करोड़ की सहायता की घोषणा

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नागालैंड के जलुकी में सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (इम्फाल) के कॉलेज ऑफ़ वेटेरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हसबैंड्री के नए प्रशासनिक-कम-शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नागालैंड के कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ₹338.83 करोड़ की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की।

मंत्री ने राज्य सरकार से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने को कहा और केंद्र की ओर से पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रत्येक जिले में वैज्ञानिक टीमों के गठन की सिफारिश की, जिनमें वैज्ञानिकों, केवीके अधिकारियों, विश्वविद्यालय विशेषज्ञों और किसानों को शामिल किया जाए, ताकि वे हर महीने दो बार स्थानीय लोगों से मिलें और उनकी समस्याएं समझें।

चौहान ने प्राकृतिक खेती की संभावनाओं को उजागर किया और सतत कृषि के लिए केंद्र के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कॉलेज की प्रशंसा की, छात्रों को दिल्ली आमंत्रित किया ताकि वे अपने विचार साझा कर सकें और स्टार्टअप्स को केंद्र की ओर से समर्थन देने का वादा किया। किसान मेले में उन्होंने किसानों से बातचीत की, जबकि नागालैंड के राज्यपाल और उपमुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक प्रगति की सराहना की। इस आयोजन में 639 किसान और 84 अधिकारी शामिल हुए।



CEASI TIMES

2027 तक यूपी में बागवानी प्रसंस्करण को 6% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक कुल फसल क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र को 11.6% से बढ़ाकर 16% करने और उत्पादों के प्रसंस्करण को 6% से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ₹11,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे मेगा फूड-प्रोसेसिंग यूनिट और भंडारण व लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाओं का विकास होगा।



फलों और सब्जियों के लिए प्रत्येक जिले में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग से रोग-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की सामग्री प्रदान करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार पॉलीहाउस और शेड नेट्स पर सब्सिडी देकर संरक्षित खेती को 500 हेक्टेयर तक बढ़ाएगी, जिससे किसानों को ऑफ-सीजन खेती और बेहतर बाज़ार मूल्य प्राप्त होगा।

माइक्रो योजना के तहत प्रसंस्करण इकाइयों को तकनीकी व ऋण सहायता देकर उनके तेज़ विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पैदावार और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार ड्रिप और स्प्रेकलर सिंचाई पर सब्सिडी बढ़ाकर 2027 तक 9% (10 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र कवर करेगी, जो 2017-2022 में केवल 2.64% था।



मिजोरम ने हरे आर्थिक विकास के लिए ₹2.5 करोड़ के बांस प्रसंस्करण इकाइयों का शुभारंभ किया

मिजोरम राज्य सरकार ने सैरांग हॉर्टिकल्चर सेंटर में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत ₹2.52 करोड़ की लागत से स्थापित बांस प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन किया। इन इकाइयों में बांस ट्रीटमेंट और सीजनिंग प्लांट, बांस डिपो और गोदाम, तथा एक्टिवेटेड चारकोल यूनिट शामिल हैं। अधिकारियों ने बांस को तेजी से बढ़ने वाला संसाधन बताया और इस परियोजना को मिजोरम के सतत औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण कदम करार दिया।

एक्टिवेटेड चारकोल यूनिट रोजाना तीन टन चारकोल (सालाना 900 टन) और लगभग 100 लीटर सिरका उत्पादन करेगी, जिससे आसुत करने के बाद 54 लीटर परिष्कृत सिरका प्राप्त होगा। ट्रीटमेंट प्लांट बांस की उम्र 50 वर्ष तक बढ़ाएगा, जबकि डिपो उचित भंडारण और आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

तीन बांस क्लस्टर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विकसित किए गए हैं, और नॉर्थ ईस्ट केन एंड बांस डेवलपमेंट काउंसिल तकनीकी सहायता और कार्यबल प्रशिक्षण की देखरेख करेगी। ऑपरेटरों को दीर्घकालिक स्थिरता के लिए उच्च मानकों को बनाए रखना होगा।

CEASI TIMES



पंजाब लीची खेती में अग्रणी, इंग्लैंड को पहली खेप का निर्यात किया

भूमिगत जलस्तर घटने से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने लीची खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की, ताकि किसान जल-गहन धान की जगह बागवानी की ओर बढ़ें। इस कदम से न केवल जल संरक्षण होगा, बल्कि किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा। 2024 में पंजाब ने पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर से इंग्लैंड को पहली लीची की खेप भेजकर निर्यात में अग्रणी बना।

यह पहल कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और बागवानी विभाग के सहयोग से संचालित की गई, जिसमें पहली खेप ने घरेलू बाजार मूल्य से लगभग पांच गुना कीमत प्राप्त की, जिससे किसानों की रुचि बढ़ी।

पंजाब में लीची की खेती 3,250 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, और उत्पादन 13,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। पठानकोट, जो राज्य की 60% लीची उत्पादन करता है, अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। एक लीची एस्टेट अब उत्पादन, संकलन और निर्यात में सहायक है। देहरादून और कलकत्ता किस्में प्रमुख जिलों में उगाई जाती हैं, जिनसे लाभ और वैश्विक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में फलों की बागवानी क्षेत्रफल 68,541 हेक्टेयर बढ़ा

महाराष्ट्र में फलों की बागवानी क्षेत्रफल 2023-24 में 13,32,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 14,00,000 हेक्टेयर हो गया है। इस वृद्धि के पीछे आम, अनार, अमरूद, नींबू, शरीफा, नारियल और अंजीर की खेती का योगदान है। घरेलू और निर्यात की मांग के साथ राज्य की योजनाओं ने इस विस्तार को बढ़ावा दिया है। नासिक ने 5,141 हेक्टेयर के साथ बढ़त बनाई, इसके बाद अमरावती (5,088 हेक्टेयर) और पुणे (4,287 हेक्टेयर) का स्थान है।



किसानों ने खजूर, अनार और अंगूर को गल्फ मार्केट में निर्यात कर अच्छी आय हासिल की है। अप्रैल में पहली बार 14 टन अनार को समुद्र मार्ग से न्यूयॉर्क भेजा गया, जो हवाई माल ढुलाई के मुकाबले सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। संयुक्त प्रयासों से समुद्र मार्ग से परिवहन की सफलता साबित हुई है। आम, अंगूर, अनार और संतरे के लिए पांच कृषि-निर्यात क्लस्टर स्थापित किए जाने की योजना है।

उत्पादक अपनी फसलों के लिए विशेष फसल बीमा और समय पर आपदा राहत चाहते हैं, ताकि उनकी बढ़ी हुई निवेश लागत को कवर किया जा सके और ग्रामीण आय में वृद्धि हो।

फंदकर फलबाग लवगड़ योजना के तहत 27,292 किसानों को 11.9 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता मिली है। सरकार किसानों और खरीदारों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर उत्पादन और निर्यात को सुचारु बनाती है।

CEASI TIMES

हिसार के NRFMTTI को CMVR मंजूरी और NABL मान्यता मिली

हिसार में स्थित नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट (NRFMTTI) को ट्रैक्टर के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के तहत परीक्षण की मंजूरी और ट्रैक्टर तथा कॉम्बाइन हार्वेस्टर के परीक्षण के लिए NABL मान्यता प्राप्त हुई है। यह NRFMTTI की कृषि मशीनरी के उच्च मानकों पर मूल्यांकन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसे उत्तरी भारत के प्रमुख परीक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करता है।



संस्थान की उन्नत सुविधाएं और कुशल कर्मचारी फार्म उपकरण निर्माताओं के लिए तेज और प्रभावी परीक्षण सुनिश्चित करते हैं। NABL मान्यता प्राप्त CMVR प्रमाणन NRFMTTI की विश्वसनीयता बढ़ाता है, वैश्विक मानकों के अनुरूप है और हरियाणा की मशीनीकरण प्रक्रिया को समर्थन देता है। इससे भारतीय निर्माताओं को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में मदद मिलती है, जो क्षेत्र की कृषि मशीनरी क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है।

ट्रैक्टर के लिए CMVR की आधिकारिक मंजूरी के साथ—जो पहले से हार्वेस्टर के लिए थी—NRFMTTI अब निर्माताओं को एक सुविधाजनक और स्थानीय परीक्षण सेवा प्रदान करता है।



असम में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए 500 ऑफ-ग्रिड सोलर पंप लगाए जाएंगे

असम में पीएम-कुसुम योजना के घटक-बी के तहत 500 ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम (SPWPS) लगाए जाएंगे। ये पंप 1 HP से 7.5 HP क्षमता वाले होंगे और उन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जहाँ विश्वसनीय ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है। ये सोलर पंप छोटे और सीमांत किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम करेंगे।

सिंचाई के साथ-साथ, ये स्टैंडअलोन सोलर पंप दूरदराज के इलाकों में पीने के पानी और सामुदायिक जल स्रोतों तक पहुंच भी बेहतर बनाएंगे। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जगह लेने से किसानों के संचालन खर्च में कमी आएगी और डीजल पंपों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कटौती होगी।

यह परियोजना केएलके वेंचर्स द्वारा नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से संचालित की जा रही है। स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव की सेवाएं स्थानीय स्तर पर दी जाएंगी, जिससे सिस्टम सुचारू रूप से काम करते रहेंगे और असम के कृषि एवं ग्रामीण समुदायों को लगातार लाभ मिलता रहेगा।

CEASI TIMES



राष्ट्रीय मिट्टी स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का शुभारंभ, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देगा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नागपुर में 'विकसित कृषि' परामर्श के दौरान राष्ट्रीय मिट्टी स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी (NSSL) का उद्घाटन करेंगे। यह लाइब्रेरी ICAR के राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण एवं भू-उपयोग योजना ब्यूरो (नागपुर), भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्थान (भोपाल), और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली) द्वारा विकसित की गई है। NSSL, प्रिसिजन एग्रीकल्चर नेटवर्क प्रोग्राम का हिस्सा है।

NSSL पारंपरिक गीली रासायनिक जांच की जगह स्पेक्ट्रल डेटा के जरिए संपर्क रहित, तेज़ और किफायती मिट्टी विश्लेषण प्रदान करता है, जो भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में लागू होगा। लाइब्रेरी लॉन्च के साथ, ICAR-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा एक AI आधारित स्मार्ट ट्रैप भी पेश किया जाएगा, जो मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए पिंक बॉलवर्म की सटीक कीट नियंत्रण में मदद करेगा।

इस अवसर पर वरिष्ठ ICAR अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति, और महाराष्ट्र के निदेशक शामिल होंगे, साथ ही प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। यह पहल मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देगी और डिजिटल उपकरणों तथा सहयोग के माध्यम से देशभर में उत्पादकता बढ़ाएगी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने e-RUPI डिजिटल पेमेंट्स और नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में e-RUPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया, जिससे मोबाइल ई-वाउचर के जरिए तेज़ और पारदर्शी कृषि सब्सिडी ट्रांजैक्शन संभव होंगे। ये वाउचर अधिकृत इनपुट सप्लायर्स पर खर्च किए जा सकेंगे; smooth उपयोग के लिए गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। e-RUPI के साथ ही चार प्रमुख फसल-केंद्रित नीतियां भी लॉन्च की गईं।

आलू के कटाई के बाद प्रबंधन योजना के लिए 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टोरेज और ग्रेडिंग के लिए 144.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि बाजरा मिशन के तहत 2030-31 तक 68 ब्लॉकों में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाएगी।

ये पहलकदमियां किसानों की आय बढ़ाने, स्थानीय रोजगार सृजित करने और ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए तैयार की गई हैं। डिजिटल पेमेंट के साथ उच्च मूल्य और मजबूत फसलों के लिए लक्षित समर्थन देकर राज्य कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है और किसानों को आधुनिक उपकरण एवं प्रथाओं से सशक्त बनाएगा।

कीवी खेती योजना के तहत 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में 6 वर्षों में 14,000 मीट्रिक टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 9,000 किसानों को लाभ होगा। 15 करोड़ रुपये की ड्रैगन फ्रूट योजना के तहत 228 एकड़ क्षेत्र में 350 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है।



CEASI TIMES

हरियाणा सरकार राज्य की जमीन पर नेचुरल फार्मिंग डेमो ज़ोन लॉन्च करेगी

हरियाणा सरकार कैथल जिले के जथेरी गांव में 53 एकड़, 4 कनाल और 19 मरले की सरकारी जमीन को नेचुरल फार्मिंग डेमो ज़ोन में बदल देगी। इस पायलट प्रोजेक्ट में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत पट्टे पर काम कर रहे वर्तमान किरायेदार किसानों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें रासायनिक मुक्त खेती के लिए प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाएंगे।



व्यावहारिक और बढ़ाने योग्य तकनीकों को दिखाकर अधिकारी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और स्थायी तरीके से किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। यदि जथेरी पायलट सफल होता है, तो इसे पूरे हरियाणा में बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य को सरकार की जमीन पर प्राकृतिक खेती के पर्यावरण और आजीविका लाभ दिखाने वाला राष्ट्रीय मॉडल बनाया जाएगा।

यह योजना कम लागत वाली, पुनर्योजी खेती को बढ़ावा देती है, जो मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाती है और इनपुट पर निर्भरता कम करती है। इस योजना के तहत किरायेदार किसानों को कवर क्रॉपिंग, खाद बनाने और बिना सिंथेटिक रसायनों के कीट प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।



हिमाचल के मुख्यमंत्री ने राज्यव्यापी कृषि बदलाव के लिए प्राकृतिक खेती की वकालत की

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे राज्य में प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कृषि विभाग, JICA और ATMA के अधिकारियों को किसानों को सीधे समर्थन और प्रमाणन मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया। पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे जहाँ किसानों का पंजीकरण होगा, और प्रशासन के सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री ने APMC के प्रमुखों से कहा है कि वे किसानों को प्राकृतिक रूप से उगाए गेहूं, मक्का और हल्दी की बिक्री में मदद करें।

खरीद के लिए उच्च गुणवत्ता वाले साइलो बनाए जाएंगे, और प्राकृतिक गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलो की एमएसपी पहले से लागू है। कृषि विभाग भाग लेने वाले किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी वितरित करेगा, जिससे बेहतर उपज और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों में तीन मॉडल फार्मों को रेखांकित किया, और और साइटें विकसित करने की योजना बनाई। उन्होंने कई जिलों में 330 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे नियंत्रित वायुमंडलीय भंडारण सुविधाओं की समीक्षा की और 1,010 करोड़ रुपये के JICA प्रोजेक्ट के पूर्ण उपयोग पर जोर दिया।

CEASI एक्टिविटीज

नॉर्थ-ईस्ट डेयरी सम्मेलन

CEDSI ने असम सरकार के डेयरी विकास निदेशालय के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट डेयरी सम्मेलन 2025 का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और किसान समूहों से जुड़े 36 संगठनों के 150 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल हुए।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में असम सरकार के श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कल्याण चक्रवर्ती, IAS उपस्थित रहे। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग, असम सरकार के आयुक्त एवं सचिव श्री एम एस मणिवन्नन, IAS ने प्रमुख वक्ता के रूप में उद्घाटन भाषण दिया।

सम्मेलन में संगठित डेयरी प्रणालियों को मजबूत करने, आधुनिक तकनीकों को जोड़ने, ग्रामीण आजीविका के लिए कौशल विकास बढ़ाने और डेयरी मूल्य श्रृंखला में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और उच्च स्तरीय चर्चा ने यह साबित किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, मजबूत और टिकाऊ डेयरी व्यवस्था स्थापित करने का साझा सपना सभी में है। CEDSI सभी वक्ताओं, पैनलिस्टों और प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता है, जिनके योगदान से यह सम्मेलन क्षेत्रीय कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया।



CEASI एक्टिविटीज

अयोध्या में सतत गन्ना खेती को बढ़ावा

'सश्वत मिठास' परियोजना के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया, UPL SAS लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या में सतत गन्ना खेती की तकनीकों को अपनाने का कार्य कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों की जानकारी और कौशल प्रदान करना है।

एक समर्पित टीम वर्तमान खेती के तरीकों का आकलन करने और सुधार की संभावनाएं खोजने के लिए क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रही है। साथ ही, खेतों पर प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें टिकाऊ गन्ना खेती की विधियों को दिखाया जा रहा है।

ये प्रदर्शन प्लॉट किसानों को बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए व्यावहारिक उदाहरण के रूप में काम करते हैं। इनमें जल प्रबंधन, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और जैविक उर्वरकों का उपयोग शामिल है। इन प्रयासों के माध्यम से, परियोजना का लक्ष्य स्थानीय किसानों में टिकाऊ खेती के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना है ताकि उपज बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।



हम कौन हैं

"सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स (CEASI)" एक स्वायत्त संगठन है, जो "एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य करता है। ASCI, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत काम करता है और इसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, स्व-रोज़गार करने वाले पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना है। यह कार्यक्रम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए तैयार किया गया है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों का एक शीर्ष संगठन है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकानिज़ेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)

